दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 14 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 223

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे पीएम-किसान योजना की आठवीं किश्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत वित्तीय लाभ की आठवीं किश्त जारी करेंगे। इससे 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो चार-चार महीने की अवधि में 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में दिया जाता है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2021 के कार्यक्रम में हुआ संशोधन

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते पैदा हालात को देखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 को स्थगित कर दिया है, जो 27 जून, 2021 को होनी थी। अब, यह परीक्षा 10 अक्टूबर, 2021 को होगी।

मानसून के 30 मई तक केरल में दस्तक देने के आसार!

नई दिल्ली (आरएनएस)। दक्षिण-पश्चिम मानसून के इस बार 30 मई तक केरल पहुंच जाने का अनुमान है। भारतीय निजी मौसम अनुमान एजेंसी स्काईमेट ने कहा कि केरल में मानसून के दस्तक देने की सामान्य तिथि एक जून है। दक्षिण-पश्चिम मानसून दो दिन पहले केरल पहुंच सकता है तथा दीर्घावधि औसत के हिसाब से इस वर्ष भी मानसून सामान्य रहेगा। यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब मानसून सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहेगा। दीर्घावधि औसत का आकलन पूर्व वर्षों में जून से सितम्बर तक चार माह के दौरान औसत वर्षा के आधार पर किया जाता है।

कोरोना के खिलाफ तेज होगी जंग, अगले सप्ताह से लोगों को लगेगा स्पूतनिक का टीका

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। नीति आयोग ने कहा है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक भारत आ रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि हम आशांवित हैं कि अगले हफ्ते से स्पूतनिक बाजार में उपलब्ध होगी। डॉ. वीके पॉल ने कहा कि हम रूस से आई हुई तय मात्रा में स्पूतनिक वैक्सीन की बिक्री के अगले हफ्ते से शुरू होने की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी सप्लाई को लेकर प्रयास जारी रहेंगे। स्पूतनिक वैक्सीन का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा। ऐसा आकलन है कि उस समय वैक्सीन की 15.6 करोड़ डोज बनाई जाएंगी। डॉ. पॉल ने कहा कि भारत में करीब 18 करोड़ के आसपास कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए 50 लाख से ज्यादा मरीज हुए लाभांवित

नई दिल्ली (आरएनएस)। लगभग एक वर्ष में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयकी प्रमुख राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के जरिए 50 लाख (आधे करोड़ से अधिक) मरीजों की सेवा की गयी है। मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में मरीजों के लिए डॉक्टरों की दूरस्थ परामर्श सेवाएं शुरू की थीं, जबकि देश में पहले लॉकडाउन के दौरान ओपीडी बंद थे। देश के 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-संजीवनी पहल चालू है और देश भर में हरदिन लगभग 40,000 मरीज स्वास्थ्य सेवा वितरण के इस संपर्क रहित और जोखिम रहित तौर-तरीके का उपयोग कर रहे हैं।

■ **ई-संजीवनी के दो मॉड्यूल हैं-** ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी- डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म- को भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हब और स्पोक मॉडल में देश के सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर लागू किया जा रहा है। अब तक ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी को 18,000 से ज्यादा स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और 1,500 से ज्यादा हब में लागू किया गया है और दिसंबर 2022 तक टेलीमेडिसिन 1,55,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में चालू हो जाएगा। नवंबर 2019 में ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी को शुरू कर दिया गया था और 22 राज्यों ने इस डिजिटल मोडेलिटी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जहां 20 लाख के करीब मरीजों को डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। विशेषज्ञों, डॉक्टरों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित कुल मिलाकर सभी 21,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है और ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी से जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा का दूसरा मॉड्यूल ई-संजीवनीओपीडी है। इसे 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। ई-एसंजीनीओपीडी पर 350 से अधिक ओपीडी स्थापित किए गए हैं, इनमें से 300 से अधिक विशिष्ट ओपीडी हैं। 30,00,000 से अधिक मरीजों को ई-संजीवनीओपीडी के माध्यम से सेवा दी गई है, जो निशुल्क सेवा है। डिजिटल स्वास्थ्य का यह मॉड्यूल नागरिकों को उनके घर की चारदीवारी में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को सक्षम बनाता है।

महामारी शुरू होने के बाद से, मरीजों और डॉक्टरों के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा को तेजी से और व्यापक रूप से अपनाया गया है। ई-संजीवनी पहले से ही जरूरत से ज्यादा भार उठा रही देश की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की एक समानांतर धारा के रूप में प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल अप्रैल में शुरू किए जाने के समय, ई-संजीवनी की गैर-कोविड संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मॉड्यूल के रूप में परिकल्पना की गयी थी, लेकिन ई-स्वास्थ्य के मॉड्यूल के संभावित लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की खातिर ई-संजीवनी के इस्तेमाल के लिए तेजी सेप्रक्रियाएं और कार्य प्रगति तैयार की।राज्यों ने घरों में अलग-थलग रह रहे कोविड-19 के मरीजों की निगरानी और प्रबंधन के लिए ओपीडी स्थापित किए हैं। कुछ राज्य विशेष होम आइसोलेशनओपीडी को चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें मरीजों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी। ये राज्य दूरस्थ रूप से कोविड-19 की जांच संबंधी उद्देश्यों के लिए एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। कोविड मामलों के बढ़ते भार के कारण, कुछ राज्यों में ई-संजीवनीका चौबीसों घंटे इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु ई-संजीवनी पर 10 लाख से अधिक परामर्श दर्ज करने वाला पहला राज्य है। रक्षा मंत्रालय ने भी कुछ राज्यों में जनता को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया है। मोहाली में सी-डैक के केंद्र में, ई-संजीवनीके निर्माता ई-संजीवनीओपीडी में एक और नवीनसुविधा जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो ई-संजीवनीओपीडीपर नेशनलओपीडी शुरू करने में सक्षम करेगा। ये नेशनलओपीडी डॉक्टरों को देश के किसी भी हिस्से में मरीजों को दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे।

महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, बढ़ाई गई सख्तियां

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां आज से एक जून तक बढ़ा दी। मुख्य सचिव ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली 'आरटी-पीसीआर' रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो। आदेश के अनुसार, 'संवेदनशील क्षेत्रों' (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी। उसके अनुसार, माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली 'आरटी-पीसीआर' रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी। राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।

हवाई अड्डे ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता हेतु मेडिकल वस्तुओं की निर्बाधित आपूर्ति की सुनिश्चित

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड 19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई को सुदृढ़ बनाने के लिए देश भर के हवाई अड्डे प्रति दिन मेडिकल की अनिवार्य वस्तुओं तथा उपकरणों की ढुलाई कर रहे हैं। एएआई का भुवनेश्वर हवाई अडडा और इसके हितधारक 24 घंटे मेडिकल की अनिवार्य वस्तुओं तथा उपकरणों की निर्बाधित ढुलाई को सुगम बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे के जरिये 09 मई 2021 तक विभिन्न एयरलाइंस के माध्यम से कोविड टीकों के कुल 669 बक्सों (20.53 एमटी) की ढुलाई की गई है। देश में ऑक्सीजन संकट से उबरने के लिए 23 अप्रैल 2021 से 11 मई 2021 तक सी17, सी130जे, एएन32 जैसे भारतीय वायु सेना के 75 विमानों द्वारा कुल 156 खाली ऑक्सीजन टैंकर, 526ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तथा 140ऑक्सीजन सिलेंडरों की ढुलाई की गई। विभिन्न एयरलाइनों के जरिये भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के 41 भागों की ढुलाई की गई। 10 लीटर के सीमलेस सिलेंडरों के 3500 भागों और 46.7 एल सीमलेस सिलेंडरों के 1520 भागों की ढुलाई की योजना है और इस खेप के दुनिया के अन्य देशों से एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर हवाई अड्डा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुरुप कोविड-19 संबंधित सभी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहा है। हवाई अड्डे के कर्मचारी लगातार सभी यात्रियों, हितधारकों, आगंतुकों, कर्मचारियों आदि से कोविड उपयुक्त बर्ताव का हमेशा पालन करने और कम से कम भीड़भाड़ होने से बचाने के लिए अलग अलग टाइमिंग बनाये रखने का आग्रह कर रहे हैं।

आईआईटी ने वहनीय टेक-ट्रेडिशनल इको-फ्रेंडली मोबाइल शवदाह प्रणाली विकसित की

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ ने एकगतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है।यहअपनी तरह की पहली तकनीक का उपयोग करने का दावा करता है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआंरहित शवदाह होता है। यह शवदाह के लिए जरूरी लकड़ी की आधी मात्रा का ही इस्तेमाल करता है और दहन वायु प्रणाली का उपयोग करने के चलते यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।

यह बत्ती-स्टोव प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसमें जब बत्ती जलती है तो पीली चमकती है। इसे बत्तियों के ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआंरहित नीली लौ में परिवर्तित किया जाता है। औद्योगिक परामर्श एवंप्रायोजित अनुसंधान एवं उद्योग सहभागिता (आईसीएसआरएंडआईआई) के डीन आईआईटी प्रोफेसरडॉ. हरप्रीत सिंह ने इस प्रणाली को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि शवदाह प्रणाली या भट्ठी 1044 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जो पूर्ण रोगाणुनाश सुनिश्चित करता है।

ठेले के आकार की भट्ठी में पहिये लगे होते हैं और बिना अधिक प्रयासों से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह ठेला प्राथमिक और माध्यमिक गर्म हवा प्रणाली के लिए दहन वायु से युक्त है। प्रोफेसर हरप्रीत ने आगे कहा, सामान्य लकड़ी आधारित शवदाह के लिए जरूरी 48 घंटे की तुलना में इसमें शीतलन समय सहित शरीर का निपटान 12 घंटे के भीतर हो जाता है। कम लकड़ी का इस्तेमाल कार्बन फुटप्रिंट को भी आधा कर सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्दम्य ऊष्मा भंडारण की अनुपस्थिति में इसे कम शीतलन समय की जरूरत होती है।ताप की हानिन हो और कम लकड़ी की खपतके लिए ठेले के दोनों ओर स्टेनलेस स्टील का ताप अवरोधन लगा हुआ है। इसके अलावा राख को आसानी से हटाने के लिए इसके नीचे एक ट्रे भी लगा हुआ है।

प्रोफेसर हरप्रीत ने बताया कि उन्होंने शवहाद के लिए टेक-ट्रेडिशनल मॉडल को अपनाया है, क्योंकि यह भी लकड़ी का उपयोग करता है।ऐसा लकड़ी की चिता पर शवदाह की हमारी मान्यताओं और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस मॉडल को बनाने वाले चीमा बॉयलर्स लिमिटेड के एमडी हरजिंदर सिंह चीमा ने कहा, वर्तमान में महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर इस प्रणाली को अपनाया जाता है तो यह उन लोगों के करीबी एवं प्रियजनों के सम्मानजनक शवदाह प्रदान कर सकते हैं, जो लकड़ी की व्यवस्था करने का वित्तीय बोझ वहन नहीं कर सकते हैं।

ब्रिक्स देशों के बीच पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह की हुई बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्यसमूह की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 11-12 मई, 2021 को वर्चुअल रूप में सुषमा स्वराज भवन में आयोजित हुई। भारत ने इसी साल ब्रिक्स का अध्यक्ष पद संभाला है। चर्चा में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देने, श्रम बाजारों को आकार देने, श्रमशक्ति के रूप में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार मेंघंटे या पार्ट-टाइम के हिसाब से काम करने वालों (गिग) तथा किसी संगठन से जुड़कर काम करने वालों (प्लेटफॉर्म) केरोजगार के मुद्देशामिल थे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) तथा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी (आईएसएसए) के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी और एजेंडा पर सुझाव दिये। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विशेष सचिव मती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव आरके गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं श्रमिक कल्याण महानिदेशक अजय तिवारी, संयुक्त सचिव सु कल्पना राजसिंहोट और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक रूपेश कुमार ठाकुर शामिल थे।

कोरोना वायरस की तीसरी लहर : 2 से 18 साल के बच्चों पर भी कोवैक्सीन का होगा ट्रायल, डीसीजीआई ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। हाल ही में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरों के बारे में वैज्ञानिकों ने भारत को सतर्क किया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार ने तीसरी लहर सेनिपटने की तैयारी शुरू कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के कोवाक्सिन को 2-18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2-3 नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक नीचे 18 आयु वर्ग में 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर नैदानिक परीक्षण करेगा। अब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए

वैक्सीन का ट्रायल अब 2 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण परीक्षा के बाद, डीसीजीआई ने कोविड -19 पर विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और 2-18 वर्ष की आयु वर्ग में कोवाक्सिन के 2-3 नैदानिक परीक्षण के संचालन की अनुमति दी है। भारत बायोटेक को बुधवार को बच्चों पर कोवाक्सिन के नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी।हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने इससे पहले 2 से 18 साल के आयु वर्ग में कोवाक्सिन के 2-3 नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। परीक्षण में, कोवाक्सिन शॉट इंट्रामस्क्युलर मार्ग के माध्यम से 28 दिनों में फैले दो खुराकों में दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई, जिसने इसे कुछ शर्तों के तहत चरण 2-3 नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति देने की सिफारिश की।

चीन की वैक्सीन से परहेज! मुंबई ने ड्रैगन को ग्लोबल टेंडर से किया बाहर

मुंबई (आरएनएस)। भारत-चीन के बीच रिश्तों में तनाव का असर अब कोरोना वैक्सीनेशन पर दिख रहा है। ग्लोबल टेंडर जारी करने वाले राज्य चीन की कोरोना वैक्सीन से परहेज करते नजर आ रहे हैं। मुंबई ने भी 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले से चीन को बाहर रखा गया है। मुंबई नगर निगम ने बुधवार को मुंबई में वैक्सीन की 1 करोड़ डोज की खरीद के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट जारी किया। ईओआई में शर्त शामिल है कि भारत के साथ जमीनी सीमाओं को साझा करने वाले देशों की कंपनियों की बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। मुंबई नगर निगम के इस फैसले से चीन की कोई भी कंपनी इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगी। हम केंद्र की वर्तमान नीति से अवगत नहीं हैं, लेकिन हमने चीन की कंपनियों को ईओआई में हिस्सा लेने से रोकने के लिए शर्त को टेंडर प्रक्रिया में डालने का फैसला लिया है। चीनी वैक्सीन की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के इस ईओआई के मुताबिक कंपनियों को 18 मई तक जवाब देना है। आदेश जारी होने के तीन हफ्ते के भीतर वैक्सीन की सप्लाई करनी होगी।

कंपनी को जरूरी रजिस्ट्रेशन समेत अन्य नियमों को भारत में पूरा करना होगा। इस खरीद के लिए बीएमसी के करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक अधिकारी के मुताबिक शहर को 1।50 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। नगर आयुक्त आई एस चहल ने कहा कि बीएमसी अगले 60 से 90 दिनों के भीतर मुंबई के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कोविड की पर्याप्त वैक्सीन हासिल कर लेगी।

बीएमसी ने पहले कहा था कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के साथ ही वो फाइजर, मॉडर्ना, स्पूतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन से बोली की उम्मीद करता है। 2022 फरवरी के आखिर में होने वाले नागरिक निकाय चुनावों से पहले बीएमसी को वैक्सीन की व्यवस्था करने की इजाजत देने का सरकार का निर्णय इन चुनावों को संभावित रूप से प्रभावित करेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने कहा था कि वह राज्य के सभी निगमों और अन्य नागरिक निकायों को वैक्सीन की सप्लाई करेगी।